प्रकाशन का 46 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक
साप्ताहिक समाचार
ई–पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 46 अंक – 43 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी. /93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 8 – 15 नवम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

हिमाचल में भी गुजरात घटने की संभावनाएं बढ़ी

नड्डा–शांता की चुप्पी बनी रहस्य

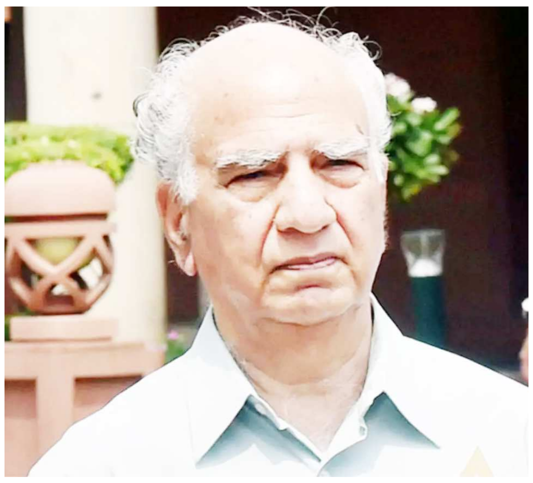

शिमला/शैल। उपचुनावों के परिणाम आने के बाद अभी तक हार के कारण की समीक्षा के लिये कोई मंथन बैठक नहीं हुई है। किसी तरह की कोई रिपोर्ट न तो प्रदेश से भेजी गयी है और ना ही केंद्र ने कोई रिपोर्ट तलब की है। इस आशय के जितने भी समाचार अब तक सामने आये हैं वह प्रदेश में ही प्लान हुए और यही तक सीमित रहे। यह स्वीकार है प्रदेश के एक बड़े नेता का। अभी तक नेतृत्व के प्रशन को लेकर केंद्र की ओर से कोई अधिकारिक ब्यान नहीं आया है और ना ही मुख्यमंत्री की ओर से ही ऐसा कोई ठोस एक्शन सामने आया है जिससे यह संदेश जाता कि नेतृत्व को लेकर हाईकमान के स्तर पर कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जिस हाईकमान ने गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में बिना किसी सार्वजनिक कारण से नेतृत्व परिवर्तन करके सबको चौंका दिया था आज वही हाईकमान प्रदेश के चारों उपचुनाव हार जाने और एक में तो पार्टी उम्मीदवार की जमानत भी ना बच पाने के बावजूद यहां नेतृत्व के प्रशन को कैसे टाल देगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस समय भाजपा के सामने अगले वर्ष के शुरू में होने वाले पांच राज्यों के चुनावों का प्रश्न सबसे बड़ा और अहम है। इसी के कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई प्रस्ताव तक पारित नहीं किया गया। फिर यह भी एक संयोग है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। बंगाल चुनावों में मिली हार की जिम्मेदारी संगठन या सरकार किसी के भी नाम नहीं लगाई जा सकी है क्योंकि सभी की भूमिकाएं बराबर रही हैं। लेकिन हिमाचल के उपचुनावों में मिली हार की पहली जिम्मेदारी न चाहते हुए भी नड्डा पर आ जाती है। क्योंकि टिकट वितरण की सारी जिम्मेदारी उस समय नड्डा पर आ गयी जब चेतन बरागटा ने यह आरोप लगाया कि प्रदेश नेतृत्व तो उनके पक्ष में था और हाईकमान ने उनका टिकट काटा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में टिकट सही उम्मीदवारों को न दिये जाने का आरोप लगा है और प्रदेश नेतृत्व ने इस पर कोई खण्डन तक जारी नही किया।

यही नहीं जब कांग्रेस में कन्हैया कुमार शामिल हुए थे और यह मुद्दा बना था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की हत्या नहीं होनी चाहिये बल्कि उसे ताकतवर बनाया जाना चाहिये तब शान्ता कुमार ने इसका समर्थन किया था। शान्ता कुमार ने अपनी आत्मकथा में भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के जो आरोप लगाये हैं उन आरोपों का केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कोई खण्डन तक नहीं आया है। आने वाले दिनों में शान्ता कुमार और उनकी आत्मकथा कांग्रेस के बड़े हथियार बन जायेंगे यह तय है। शान्ता कुमार का आशीर्वाद नड्डा और जयराम के लिए कितना और किस हद तक का है इसे प्रदेश का हर आदमी जानता है। इस पृष्ठभूमि के साथ जब शान्ता कुमार इन उपचुनावों के लिये स्टार प्रचारक बनाये गये तो समझा जा सकता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा।

इस समय प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा या यह सवाल अब खत्म हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा है क्योंकि हाईकमान की ओर से अभी तक ऐसा कोई ब्यान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन उपचुनावों में करीब सभी मंत्रियों की जिम्मेदारीयां लगी थी। प्रदेश के बीस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है जिसमें केवल मण्डी के आठ क्षेत्रों में ही भाजपा को बढ़त मिली है बारह चुनाव क्षेत्रों में पार्टी हारी है। मण्डी में भी इसलिये जीत मिली की मुख्यमंत्री इसी जिले से हैं और अभी एक वर्ष सरकार रहनी है। परंतु अब बारह क्षेत्रों में हार से यही स्पष्ट संदेश जाता है कि आगे सरकार नहीं बन पायेगी। इस हार का असर मण्डी पर भी पड़ेगा यह तय है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि एक

शेष पृष्ठ 8 पर........

कांग्रेस की जनचेतना यात्रा से उठते सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश में हुए उपचुनाव में चारों सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने जन चेतना यात्रा शुरू की है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जायेंगे । राठौड़ जहां भी जा रहे हैं उन्हें वहां पर कार्यकर्ताओं और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन प्रमाणित कर रहा है जनता सही में वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित किया हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर जनता को और जागरूक किया जा रहा है। इस यात्रा में स्थानीय नेताओं और संबंधित जिला के नेताओं को शामिल किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में इस तरह की यात्रा आवश्यक है ताकि जनता ने जो नाराजगी इन उपचुनावों में सरकार के प्रति दिखाई है उसे अगले चुनावों तक बरकरार रखा जा सके । यह यात्रा जहां कांग्रेस की राजनीतिक आवश्यकता है वहीं पर इस यात्रा से कुछ सवाल भी उभरे हैं।

यह सही है कि इस समय महंगाई और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान है। लेकिन कल को यदि महंगाई पर सरकार नियंत्रण कर लेती है और कुछ आवश्यक चीजों की कीमतें घटा दी जाती हैं तब भी क्या यह नाराजगी बरकरार रहेगी? इस सवाल पर यात्रा में यह नहीं बताया जा रहा है कि इस महंगाई और बेरोजगारी के मूल कारण क्या है। वह कौन सी आर्थिक नीतियां हैं जिनके कारण यह सब हो रहा है। जनता को यह नहीं बताया जा रहा है कि आज बैंकों का एनपीए ढाई लाख करोड़ से बढ़कर दस खरब करोड़ क्यों हो गया है। सरकार कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रही है। इन कानूनों का दुष्प्रभाव किसान ही नहीं हर आदमी पर पड़ेगा। जनता को बुनियादी मुद्दों पर जागरूक करने की आवश्यकता है जो शायद नहीं किया जा रहा है।

इससे भी बड़ा सवाल यह है की इस यात्रा में कुलदीप राठौर के साथ प्रदेश स्तर के अन्य नेता एक टीम की शक्ल में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस समय कांग्रेस से यह सवाल पूछा ही जाएगा कि उसका अगला नेता कौन है। मुख्यमंत्री का संभावित चेहरा कौन होगा? यदि इस यात्रा में राठौर के साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सी डब्लयू सी सदस्य आशा कुमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू और कौल सिंह ठाकुर तथा मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हर्षवर्धन चौहान साथ होते तो इससे टीम की शक्ल में पार्टी की एकजुटता का संदेश जाता। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में यह सवाल उछले।

हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास जारी:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि कोरोना काल की कठिन चुनौतियों का एकजुटता से सामना करने के बाद हिमाचल विकास के पथ पर फिर से तेजी से अग्रसर है। विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर वह व्यक्तिगत तौर पर भी अपना योगदान देकर इस पहाड़ी प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं।

राज्यपाल ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मलेन की अध्यक्षता राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की। इस अवसर पर उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, गृह मन्त्री अमित शाह, सभी राज्यों के राज्यपाल व उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

आर्लेकर ने कहा की राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लोगों को कोरोना की पहली खुराक देने के मामले में हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा की प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी कोशिश रहेगी कि हर जिले की विशेषता पर आधारित मेलों का आयोजन कर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी उचित मंच व बाजार उपलब्ध करवा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की परिकल्पना को भी साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण उनकी प्राथमिकताओं में है।

उन्होंने कहा कि कामकाज को पारदर्शी, तीव्र, सुगम व सुचारू बनाने के लिए 22 अक्तूबर, 2021 से हिमाचल प्रदेश राजभवन को पूरी तरह से ई-ऑफिस में बदल दिया गया है, जिसके तहत सारा कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा केन्द्रों में गुणात्मक शिक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश सरकार के हर घर पाठशाला कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने कोरोना महामारी के कारण लाकडाउन के दौरान विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य सुचारू बनाये रखने के लिए अप्रैल 2020 से अपनी तरह का यह अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लगभग 8 लाख बच्चे लाभान्वित हुए।

राज्यपाल ने कहा की राज्य में प्राकृतिक खेती को काफी विस्तार दिया जा चुका है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत 1.5 लाख से अधिक किसान इसे अपना चुके हैं। प्रदेश की कुल 1.2 लाख बीघा जमीन पर यह कृषि की जा रही है। उन्होंने बताया कि वह सामाजिक समरसता की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मानवता के कार्यों में राजभवन पूरी तरह सक्रिय है और रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं के माध्यम से उनकी कोशिश है कि जरूरतमंद और पात्र लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य रेडक्रॉस, जिला प्रशासन और इण्डियन रेडक्रॉस के साथ नालागढ़ में अल्ट्रामाडर्न ब्लड बैंक विकसित कर रही है, जिसे शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जाएगा।

उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी व सेवन का मामले भी उठाया तथा कहा कि इस अंकुश लगाने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा की राज्यपाल के तौर पर उनकी कोशिश रहेगी कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और समाज के सबसे निचले स्तर तक व्यक्ति लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि करीब चार माह की अल्पावधि में उन्होंने हिमाचल में सामाजिक सरोकार के विभिन्न प्रकल्पों को लक्षित कर समाज को दिशा देने की कोशिश की है।

देश के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि भारत पुनः विश्वगुरू बने यह हर भारतीय का स्वप्न है और आज इसे हकीकत में परिवर्तित करने का समय आ गया है। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें किसी न किसी रूप में योगदान करने का प्रण लेना चाहिए।

सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला
द्वारा आयोजित संगोष्ठी
स्वाधीनता के 75 वर्ष
दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

वह सुनील उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर गयेटी थियेटर में सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आजादी के 75 वर्ष विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज देश में उत्साह का महौल है परन्तु हमें यह चिन्तन करने की आवश्यकता है कि हमने 75 वर्षों में क्या खोया और क्या हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हजारों वर्षों से समृद्ध संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि हमें 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आजादी के बाद अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने अन्य देशों से आशाएं रखीं और उनके मॉडल अनुकरण करना आरम्भ किया। उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व लोगों के मस्तिष्क में देश प्रेम की जो भावना थी, उसमें आजादी के उपरान्त कहीं कमी नजर आने लगी। इसके प्रति आत्ममंथन करने की नितांत आवश्यकता रही।

राज्यपाल ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि इस वातावरण को बदलने के लिए प्रयास करें। आज देश को सशक्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है और देश में अलग तरह के वातावरण के निर्माण हुआ है। इस बदले परिवेश में हम सभी को देश के विकास के लिए अपना योगदान देना करना चाहिए।

इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सात स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सुनील उपाध्याय ने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हिमाचल में मजबूत संगठन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज देश में पाश्चात्य विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमें अपने गौरवशाली इतिहास का अध्ययन करने और उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है।

विशिष्ट अतिथि आशीष चौहान ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. सुनील कुमार गुप्ता ने राज्यपाल का स्वागत किया और ट्रस्ट की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

ट्रस्ट के सचिव डॉ. सुरेन्द्र शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रो. सिकन्दर कुमार, गुड़िया सक्षम बोर्ड की उपाध्यक्षा रूपा शर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य डॉ. नागेश ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस लोगों की स्वतंत्र प्रेस के प्रति प्रतिबद्धता को और भी सुदृढ़ करता है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रहा है, वहीं बदलते दौर के साथ इस क्षेत्र में नई चुनौतियां भी उनके समक्ष आई हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि मीडिया भविष्य में भी अपने उच्च आदर्शों के अनुरूप समाज के हितों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक ढंग से उठाते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहेगा और सरकार व जनता के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता रहेगा।

दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर देने की जरूरतः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें अवसर देने की आवश्यकता है। उनके पास अलग प्रकार की प्रतिभा है।

वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं उमंग फाउंडेशन शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्रावासों में रह रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को हॉस्टल फीस माफ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का अहम हिस्सा हैं और उनके पास विशेष प्रतिभा है। इनमें से कई अपने महत्वपूर्ण योगदान से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर यह पहल की है। राज्यपाल ने उमंग फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की भी दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं के लिए सराहना की तथा कहा कि इस दिशा में और कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय सभागार में रैंप निर्मित करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं उप-कुलपति प्रो. सिकन्दर कुमार ने कहा हमें संवेदनशील होकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये कार्य करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में लीगल सेल गठित कर न्याय देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं यू.जी.सी. सदस्य प्रो. नागेश ठाकुर ने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिव्यांगजनों ने समाज में मिसाल कायम की है। उन्हें सुविधा देना हम सब का कर्तव्य है ताकि वह आगे बढ़ सकें। उन्होंने उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने फाउंडेशन की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश का शायद पहला विश्वविद्यालय होगा जो विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के अनुकूल है और ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रहा है।

इस अवसर पर दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों ने अपने विचार भी साझा किए तथा गायन के माध्यम से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया।

स्मार्ट सिटी के कार्य तय समय में पूरे करे हिमुडा:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री एवं हिमुडा के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि शिमला के लोअर बाजार में बन रही दुकानों के कार्य को जल्दी पूरा करें।

शहरी विकास मंत्री ने बताया की दुकानों का कार्य अगले दस दिन में पूरा किया जायेगा और दिसंबर माह में दुकानों का आबंटन भी कर दिया जायेगा। उन्होंने लोअर बाजार में टनल और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने टनल के पास शौचालय निर्माण के कार्य में तेज़ी लाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर हिमुडा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer Jawali Division HP PWD Jawali on behalf of the Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids,in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work	Estimated cost (Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender	Deadline for submission of Bid
1. Construction of Jawali Sunehar Thanger Pharian Kardial road Km. 0/0 to 5/500 under SCSP(SH:- Providing and laying Cement concrete pavement at various reaches between Km. 1/0 to 3/500).	535275/-	10700/-	One month	350/-	27.11.2021

The bidders are advised to note other details of tenders from the Department website www.hptenders.gov.in opened on.. 29.11.2021

Adv. No. 4740/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

21 नवम्बर से शुरू होगा जनमंच कार्यक्रम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसम्बर, 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें पांच बैठकें होंगी।

बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवम्बर, 2021 से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवम्बर से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50 प्रतिशत मानदण्ड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवम्बर, 2021 से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुति दी।

मंत्रिमण्डल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के कुलपतियों तथा सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मण्डी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने पर कार्य किया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृति 1 अप्रैल, 2021 से 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी। अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपये के स्थान पर 40 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार रुपये के स्थान पर 45 हजार रुपये और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थीं। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगन्धित पौधों की प्रजाजियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया।

इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के सम्बंध में एक प्रस्तुति भी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की।

स्मार्ट सिटी के अधिकतर काम 31 मार्च तक होंगे पूरे : भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अधिकतर कार्य जिनमे पार्किंग और ओवर ब्रिज भी शामिल हैं, 31 मार्च 2022 तक पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में गिरि नदी में गाद की समस्या के समाधान के लिए टयूबसेटलर 15 दिसंबर तक काम करना शुरू करेंगे।

सुरेश भारद्वाज शिमला नगर निगम और शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी और अमृत के कार्यो की समीक्षा करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पहले अमृत और उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास के काम चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर कि सड़कों को चैड़ा करने और छोटे पार्किंग स्थल विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अमृत मिशन के अंतर्गत लगभग 150 गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग का काम 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जायेगा। मंत्री ने संजौली चैक ओवर ब्रिज को 31 मार्च 2022 और संजौली महाविद्यालय के नीच बन रहे ओवर ब्रिज को अगले माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संजौली फुट ओवर ब्रिज में रैंप बनाने और एक्सेलरेटर की सम्भावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

मंत्री ने रानी लक्ष्मी बाई पार्क (लेडीज पार्क) को बड़े शहरों के एम्यूजमेंट पार्क की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस पार्क के लिए लगभग 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि पार्क में सेल्फी प्वाइंट, बच्चों के खेलने के लिए जरूरी सामान लगा कर विकसित किया जाए।

शिमला शहर के 5 वार्डों में 24 घंटे पानी की सप्लाई कि योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक 24 घंटे पानी मिलना शुरू हो जायेगा।

बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत बन रही 450 गाड़ियों की 30 छोटी पार्किंग पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न वार्डों में बन रही ये पार्किंग 31 मार्च, 2022 तक बन कर तैयार हो जायेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब एक हजार करोड़ के कार्य शिमला में किए जायेंगे जिनमें से अधिकतर पर कार्य जारी है।

बैठक में निदेशक शहरी विकास मनमोहन शर्मा, शिमला नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायालयों में लम्बित मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न विभाग बेहतर समन्वय बनाएंः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के सभी विभागों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके तथा प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहे। मुख्यमंत्री अदालतों में लम्बित मामलों के दृष्टिगत प्रशासनिक सचिवों और महाधिवक्ता के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लिटिगेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया है और इस सॉफ्टवेयर में सभी अदालती मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महत्वकांक्षी परियोजनाओं से सम्बन्धित और प्रमुखता वाले मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को महाधिवक्ता के कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि अदालतों में मामलों को शीघ्र सुलझाया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जेओए आईटी, जेबीटी इत्यादि से सम्बन्धित अदालती मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों पर लगी रोक को हटाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने माननीय न्यायालयों से इन मामलों को सुलझाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्वीकृतियों और अदालतों में लम्बित मामलों के कारण कई विकासात्मक परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी मामलों में अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आम लोगों को लाभ होगा बल्कि परियोजना सम्बन्धी लागत से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न लम्बित मामलों की निगरानी के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी और अधिक समन्वय और समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

प्रधान सचिव गृह रजनीश ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

महाधिवक्ता अशोक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जेसी शर्मा, प्रधान सचिव सुभाषीश पांडा, सचिव विकास लाबरू, राजीव शर्मा और अमिताभ अवस्थी भी बैठक में उपस्थित थे।

विभागीय परीक्षा 14 से 23 फरवरी, 2022 तक आयोजित की जाएंगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन 14 से 23 फरवरी, 2022 तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, भारतीय वन सेवाएं/ हिमाचल प्रदेश वन सेवाएं के अधिकारियों, अन्य सभी राजपत्रित अधिकारियों और पात्र अराजपत्रित अधिकारियों (अधीक्षक वर्ग-2 और वरिष्ठ सहायक) तकनीकी और गैर-तकनीकी, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी और कराधान निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के (वर्ग-2 अधिकारी/कर्मचारी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम के अभियन्ता अधिकारियों (सिविल/इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल), हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के सहायक अभियन्ताओं (सिविल/वरिष्ठ प्रबंधक) और राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए विभागीय कानूनगो परीक्षा आयोजित की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि केवल पेपर नम्बर-1 (वित्तीय प्रशासन) परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजकीय महाविद्यालय संजौली, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं राजकीय महाविद्यालय संजौली शिमला में ही आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन 1 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक जमा करवा सकते हैं। प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन तभी मान्य होंगे जब उन्हें विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों को 10 जनवरी, 2022 तक अनुमोदित कर पाएंगे और इसके उपरान्त विभागाध्यक्ष की विंडो स्वतः ही बंद हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदन फॉर्म हिपा की वेबसाइट www.hipashimla.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रदेश में कुष्ठ रोगियों का किया जा रहा निःशुल्क उपचार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में कुष्ठ रोगियों के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के मामलों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना और रोगियों को पूर्ण मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इस रोग का समय पर पता चल जाने और समय पर उपचार मिलने से प्रभावित व्यक्तियों में जहां विकलांगता आने से रोका जा सकता है वहीं इस रोग के आगे फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यदि इस रोग के उपचार का कोर्स समय पर पूरा किया जाए तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है। उन्होंने कहा कि यह रोग छींकने और नाक बहने के दौरान बूंदों के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ लोगों में फैलता है, इसलिए इसे फैलने से रोकना और ऐसे रोगियों का पता लगा ऐसे मरीजों का उपचार करना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षणों जैसे त्वचा पर हाइपोपिगमेंटेड पैच, नसों का मोटा होना और छूने पर दर्द, घावों का उपचार न होना, त्वचा पर मोटी चमकदार गांठें, वस्तुओं को पकड़ते समय हाथों की कमजोरी आदि के बारे में सतर्क रहना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कुष्ठ रोग के सालाना 120 से 150 मामले दर्ज किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी कुष्ठ रोग से संबंधित सक्रिय मामलों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों के परिवार के सदस्यों की भी कुष्ठ रोग से संबंधित लक्षणों की जांच की जाती है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुष्ठ रोग के 101 सक्रिय मामले हैं। इन सभी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है और किसी प्रकार की चोट से बचने के लिए वर्ष में दो बार एमसीआर के जूते दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग के सभी मरीजों, जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता होती है उन्हें सर्जरी के दौरान और सर्जरी के पश्चात मजदूरी संबंधी क्षति की पूर्ति के लिए एकमुश्त 8000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा सभी कुष्ठ रोगियों को प्रतिमाह 750 रुपये पेंशन दी जाती है।

राज्य समीक्षा समिति की बैठक में 117.14 करोड़ रुपये के 24 प्रस्तावों को स्वीकृति

शिमला/शैल। राज्य समीक्षा समिति (राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की उप-समिति) की 31वीं बैठक निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। समिति ने बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने व वर्तमान इकाइयों के विस्तार के 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। 18 प्रस्तावों की राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण के विचार व अनुमोदन के लिए अनुशंसा की गई।

राज्य समीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों पर लगभग 117.14 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 989 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

समिति द्वारा राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण को अनुशंसित प्रस्तावों के माध्यम से 1173.99 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्वावित है। इससे 2102 लोगों को रोजगार मिलेगा।

संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है।....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या कंगना प्रयोग सफल हो पायेगा

सिने तारिका हिमाचल की बेटी पद्मश्री कंगना रनौत ने 1947 में अंग्रेजों के तीन सौ वर्ष के शासन से मिली आजादी को भीख की संज्ञा दी है। कंगना के मुताबिक देश को सही में आजादी 2014 मे मिली है। कंगना के इस ब्यान से पूरे देश में प्रतिक्रियाएं उभरी हैं। ब्यान को स्वतन्त्रता सेनानियों से लेकर संविधान का अपमान माना जा रहा है। पद्मश्री वापस लेने और देशद्रोह का मुकद्दमा दायर करने की मांग उठ रही है। कंगना के ब्यान पर सभी गैर भाजपा दल आक्रोषित हैं। केवल भाजपा ही इस ब्यान पर खामोश है। भाजपा की खामोशी से ही इस ब्यान के पीछे की राजनीति स्पष्ट हो जाती है। कंगना की उम्र और उसकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभिनेता अभिनेत्रियां अधिकांश में दूसरों द्वारा लिखी स्क्रीप्ट पर ही अभिनय करते हैं और उसी से अवार्ड प्राप्त कर लेते हैं। ग्लैमर की दुनिया के लोगों को अपना प्रचार और पैसा चाहिए होता है और इसके लिए वह किसी की भी टयून पर डांस कर देते हैं। फिर जब से राजनेताओं को सुनने के लिए आने में जनता की रूची कम होने लगी है तब से राजनेता भीड़ जुटाने के लिए अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और खिलाड़ियों का प्रयोग करने लगे हैं। लम्बे अरसे से यह लोग राजनीतिक दलों और मनोनयन के माध्यम से संसद में आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कितने लोगों का संवैधानिक योगदान रहा है तो बड़ा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं मिलता है। कंगना रणौत के ब्यान को भी इसी परिपेक्ष में देखना होगा। कंगना को जो पटकथा दी गयी उसने उसका पाठ कर दिया। अन्यथा जिस अभिनेत्री को झांसी की रानी के किरदार के लिए पदम श्री मिला हैं उससे आजादी को भीख करार देने का ब्यान आना अपने में ही एक अंत: विरोध हो जाता है।

ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इस समय कंगना से यह ब्यान क्यों दिलाया गया। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण पर कंगना जिस तरह से मुखर हुई और उस मुखरता के बाद जो अदालती मामलों का सिलसिला शुरू हुआ है उससे बाहर निकलना कठिन होता जा रहा है। कंगना ने केस ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। उस दौरान हिमाचल भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व उसके गिर्द इक्कठा हो गया था। शिमला में उसके लिये प्रदर्शन किया गया था। मण्डी की लोकसभा सीट से कंगना के प्रत्याशी होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। पद्मश्री मिलने पर मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बधाई दी है। अब उसे राज्यसभा में भेजने की चर्चाएं भी कुछ हल्कों में चल पड़ी है। यह सब प्रमाणित करता है कि कंगना को भाजपा समर्थन हासिल है। 2014 में जिस तरह से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता में आयी थी उसका सच सामने आ चुका है कि एक भी मामले में कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। भ्रष्टाचार के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा गौ रक्षा और लव जिहाद का सत्ता में आने के बाद उठाया। इन मुद्दों से उभरा आक्रोष भीड़ हिंसा तक जा पहुंचा। इसके बाद नागरिकता कानून में संशोधन और 370 तथा तीन तलाक हटाने के मुद्दों का प्रयोग हुआ। राम मंदिर पर फैसला आया और निर्माण शुरू हुआ। लेकिन सारे मुद्दों का अंतिम परिणाम बंगाल के चुनावों में सामने आया। जहां **"दो मई दीदी गई"** के नारे की हवा निकल गयी। अब उप चुनावों के परिणामों ने भी भाजपा के सारे दावों का जमीनी सच जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।

इस समय भाजपा के सामने अगले वर्ष के शुरू में होने वाले पांच राज्यों के चुनाव हैं। इन चुनावों का कितना दबाव है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लंबे अन्तराल के बाद भी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न तो कोई किसी भी तरह का प्रस्ताव तक पारित नहीं हुआ। यहां तक की उपचुनावों के परिणामों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। 2014 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं हरेक में देश के अन्दर वैचारिक विभाजन खड़ा करने की रणनीति पर काम किया गया। जबकि 2014 से लेकर अब तक के लिए सारे आर्थिक फैसलों ने आम आदमी को लगातार कमजोर किया है। केवल वैचारिक विभाजन से सफलता मिलती रही। आज किसान आन्दोलन ने सरकारके पावों से सारी जमीन खींच ली है। ऐसे में कंगना रणौत जैसी कमजोर बैसाखियों के सहारे फिर से एक वैचारिक विभाजन की जमीन तैयार करने का प्रयास किया गया है।

आत्मनिर्भरता की प्रतीक बनी मुख्यमंत्री एक बीघा योजना

शिमला। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को विशेष अधिमान दे रही है, जिसके फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन कर उभरा है। प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्वयंसहायता समूह की महिलाओं को खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 21 मई, 2020 को इस महत्त्वकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं तथा स्वयंसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ उन्हें बैकयार्ड किचन गार्डनिंग के लिए प्रशिक्षित करना है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के बीच एक अभिसरण योजना है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अतंर्गत बने स्वयं सहायता समूह की कोई भी महिला सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह एक लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना आवश्यक है।

प्रदेश में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अनुसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किचन गार्डन के विकास से पोषणयुक्त सब्जियों और फलों का उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ उत्पादित उत्पादों को खुले बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ अर्जित कर रही है।

मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत प्रदेश में भूमि सुधार, नर्सरी उत्पादन, फलदार वृक्षारोपण, केंचुआ खाद गढा निर्माण, अजोला पिट निर्माण, सिंचाई और जल संचयन संरचना निर्माण और गौशाला निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2020-21 में इस योजना के अन्तर्गत 11,254 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 1,690 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक विभिन्न कार्यों पर लगभग 17.91 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है।

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस योजना के अन्तर्गत 2281 कार्य स्वीकृति किए गए, जिनमें से 1045 का कार्य आरम्भ किए जा चुका है और चालू वित्त वर्ष में अब तक 852 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 4 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

यह योजना प्रदेश में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो रही है। जिला सिरमौर के राजगढ़ खंड के शिरगुल महाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है। यह योजना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। अदरक के औषधीय गुणों को देखते हुए यह स्वयं सहायता समूह अदरक की खेती करना चाहता था परन्तु धन की कमी उनके इस कार्य में बाधा बन रही थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जब मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने राजगढ़ विकास खंड में जाकर इस योजना के लिए आवेदन किया। इस योजना से मिली आर्थिक सहायता का उपयोग कर इस समूह की महिलाओं ने बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर अदरक की खेती की शुरूआत की। इस स्वयं सहायता समूह की मेहनत रंग लायी और उनके सात सदस्यों के इस समूह ने हिम ईरा साप्ताहिक बाजार में 50 हजार रुपये के अदरक की बिक्री की। अपने पहले प्रयास पर मिली सफलता से उत्साहित होकर अब इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मूली की खेती की है और शीघ्र ही हिम ईरा साप्ताहिक बाजार में यह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने महज 7-8 महीनों के भीतर जैविक खेती को अपनाकर इन उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाया है। यह स्वयं सहायता समूह प्रदेश की अन्य स्वयं सहायता समूहों को प्रगति का मार्ग दिखा रहा है। प्रदेश में शिरगुल महाराज स्वयं सहायता समूह का सफल उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री एक बीघा योजना किस प्रकार महिलाओं के जीवन में खुशहाली ला रही है। यह छोटी सी शुरुआत लम्बी विकास यात्रा का आगाज़ है।

दीन दुखियों को हिमाचल सरकार का 'सहारा'

शिमला। प्रदेश सरकार हर हिमाचली के लिए दुख तकलीफ की किसी भी परिस्थिति में सहारा बन कर खड़ी है। बीमार-लाचार लोगों की सहायता के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना आरंभ की है। इस योजना में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए गंभीर रोगों में हर महीने 3 हजार रुपये उनके बैंक खाते में डाले जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य लंबी अवधि तक उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिवारों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। यह जानकारी मंडी जिला में लोगों को सरकारी योजनाओं बारे जागरूक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे चार दिवसीय विशेष प्रचार अभियान के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रमों में गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दी गई।

कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि सहारा योजना का पात्र बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र, बीमारी के दस्तावेज, स्थाई पते का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि, बीपीएल प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पूर्ण जानकारी।

उक्त दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सीधे सम्पर्क करें। नाट्य दलों द्वारा विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्गो के लाभ के लिए चलाई योजनाओं की जानकारी दी गई। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ कर इन वर्गो का सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित किया है।

कार्यक्रम के तहत संवाद युवा मंडल मंडी द्वारा निचली बैहली व पलोटा, जालपा कला मंच स्यांह द्वारा समराहण व बटाहर, शांगल म्यूजिकल ग्रुप गुलाड़ द्वारा सिलणू, सरस्वति म्यूजिकल ग्रुप धर्मपुर द्वारा तुलाह व उटपुर जबकि सांस्कृतिक लोक मंच करसोग द्वारा राकणी व मेहरन में कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

एक अन्वेषक से प्रभावशाली प्रवर्तक बनने की यात्रा

शिमला। सुंदरम वर्मा, जमीनी स्तर के अन्वेषक से सामाजिक कार्यकर्ता और प्रख्यात पर्यावरणविद् बने, जिन्होंने राजस्थान के शुष्क शेखावती क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पेड़ों को विकसित किया, जिसमें पानी की बचत वाली तकनीक ’ड्राईलैंड एग्रोफॉरेस्ट्री’ का उपयोग किया जाता है, जिस पद्धति में प्रति पेड़ केवल 1 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा इस सप्ताह देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए अन्वेषक आज न केवल अपने नवाचार के लिए, बल्कि अन्य अन्वेषकों की खोज करने और उनको अपनी सफलता से प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं।

सुंदरम वर्मा, राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव दांटा (रामगढ़) के मूल निवासी हैं, जिन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, जिसे ग्रीन ग्रासरूट प्लांटेशन तकनीक के माध्यम से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और शुष्क क्षेत्र की फसलों पर अनुसंधान करने के लिए बनाया गया है। इसे ‘रेगिस्तान को हरा-भरा करने’ वाली पहल के अंतर्गत पेड़ लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था।

इस तकनीक में पौधों के लिए उनके पूरे जीवनकाल में केवल एक लीटर जल का ही उपयोग किया जाता है और शुष्क, अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण के साथ-साथ कृषिवानिकी के लिए सबसे उपयुक्त समाधान प्रदान करती है, जिससे भूमि प्रबंधन, राजस्व और चिरस्थायी आजीविका का निर्माण होता है।

वे एक किसान है-एक मजबूत अन्वेषण के प्रजनक हैं, जिसके माध्यम से उनका काम परिभाषित होता है। उनके पौधों की उन्नत किस्म- सिसर एरीटिनम एल. है, जिसे आमतौर पर ‘काबुली चना-एसआर-1’ के नाम से जाना जाता है। मीडियम बोल्ड सीड (उच्च परीक्षण वेट) और उपज तथा कीट प्रतिरोधता के मामले में बेहतर होने के कारण यह अलग है और इसे प्रोटक्शन ऑफ़ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (पीपीवी एंड एफआरए) के साथ सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है।

इसके अलावा, उनको अन्य उन्नत पौधों की किस्मों का श्रेय भी जाता हैं जैसे उच्च उपज वाली ‘ग्वार (क्लस्टर बीन)-एसआर-23’ जो कि शुष्क और अर्ध-शुष्क दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है लेकिन उसके लिए सबसे उपयुद्ध रेतीली/रेतीली दोमट मिट्टी है। इसके अलावा, ‘मोठ बीन (एसआर-1)’ है जो एक छोटी अवधि (60-65 दिन) वाली किस्म है, जो प्रमुख कीटों और बीमारियों के खिलाफ उपज और प्रतिरोधता के मामले में अन्य व्यावसायिक किस्मों से बेहतर है। वे कई वर्षों से विभिन्न फसलों की स्थानीय उपज/किस्मों का संरक्षण और खेती कर रहे हैं।

हालांकि उन्हें स्नातक की पढ़ाई पूरा होने के तुरंत बाद ही रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया और फसल सुधार के लिए कृषि आधारित अनुसंधान तथा शुष्क क्षेत्र की फसलों में कृषि जैव विविधता का संरक्षण करने वाले अपने जुनून और रुचि के क्षेत्र को जारी रखा।

वे एनआईएफ की स्थापना के बाद से ही उसके शुरुआती सहयोगियों में से एक हैं। वर्तमान समय में वे इसके जनरल बॉडी के सदस्य हैं और अपने जैसे अन्य अन्वेषकों की खोज करते है। जगदीश पारिख, एक अन्य जमीनी अन्वेषक, जिन्हें कीट और जलवायु प्रतिरोधी फूलगोभी की किस्म विकसित करने में योगदान देने के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें लगभग दो दशक पहले एनआईएफ की ओर से सुंदरम वर्मा द्वारा खोजा गया था। इसके अलावा, एनआईएफ की ओर से सुंदरम वर्मा द्वारा संतोष पाचर (गाजर किस्म), मदनलाल कुमावत (मल्टी क्रॉप थ्रेसर), सुभाष ओला (कंडेनसेट एंड हीट रिकवरी सिस्टम), यूसुफ खान (मूंगफली खोदने वाला), राय सिंह दहिया (बायो मास गैसीफायर सिस्टम) जैसे अन्वेषकों का पता लगाया गया। बाद में उन्हें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा खोजे गए कुछ अन्वेषकों को राष्ट्रपति भवन में इनोवेशन स्कॉलर इन-रेजिडेंस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

मेरी पूरी फसल अनुसंधान जैव विविधता से है और मैं मानता हूं की जैव विविधता प्रकृति की आत्मा एवं हमारा भविष्य है। हमें इसमें से केवल वर्तमान ढूंढ़ना है और हर कीमत पर इसे बचाए रखना है।

पर्यावरणविद सुंदरम वर्मा, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए इनोवेटिव ग्रीन ग्रासरूट प्लांटेशन तकनीक के माध्यम से पेड़ लगाते हुए

देश भर में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का स्कूलों और छात्रों की बड़ी भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक आयोजन

शिमला। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। शुरुआती अनुमानों के तहत, सर्वेक्षण में 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों केलगभग 96 प्रतिशत स्कूलों से और कक्षा 3, 5, 8 व 10 के लगभग 92 प्रतिशत बच्चों से नमूने प्राप्त हुए। राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण (एनएएस) इस बात की एक गहन समझ विकसित करने के क्रम में सूचनाएं जुटाने की एक प्रक्रिया है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, समझते हैं और अपने शैक्षणिक अनुभवों के परिणामस्वरूप अपने ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। यह प्रक्रिया व्यवस्थित हस्तक्षेपों के माध्यम से अंततः विद्यार्थियों के सीखने और विकास के परिणामों में सुधार के साथ समाप्त होगी। उपलब्धि सर्वेक्षण नमूना स्कूलों में उपलब्ध शिक्षा के विभिन्न माध्यमों में आयोजित किया गया।

एनएएस वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया उपलब्धि सर्वेक्षण है। एनएएस की इस प्रक्रिया में उपकरण विकास, नमूना डिजाइन और परीक्षा का वास्तविक प्रबंधन शामिल है। ग्रेड वार विषय केंद्रित शिक्षा के परिणामों की पहचान की गई है, जिनका एनएएस के माध्यम से आकलन किया गया है। उपकरणों को कुछ इस तरह से विकसित किया गया है कि यह वैज्ञानिक शिक्षा के परिणामों का आकलन कर सकता है। एक नोडल शैक्षणिक संस्था होने के नाते, एनसीईआरटी ने उपकरण विकास, परीक्षा कराई है, परीक्षा सामग्रियों को अंतिम रूप दिया है। एक नमूना आधारित सर्वेक्षण होने के कारण, डाटा को ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रमाणिक बनाने के लिए नमूना डिजाइन महत्वपूर्ण है। नमूना डिजाइन, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के तहत एक वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग के बाहर की थर्ड पार्टी मूल्यांकन एजेंसी होने के नाते सीबीएसई ने उच्च स्तर की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भागीदारी में नमूना स्कूलों में परीक्षा का वास्तविक प्रबंधन किया है।

छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों की विभिन्न व्यवस्थाओं और योजनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण के अलावा छात्र प्रश्नावली, शिक्षकों की प्रश्नावली और स्कूल प्रश्नावली भी प्राप्त की गई हैं। इससे शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से समझने के लिए पृष्ठभूमि, शिक्षक प्रशिक्षण, ग्रामीण- शहरी, ऑनलाइन शिक्षा की प्रभावशीलता आदि के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) जारी होने के बाद एनएएस 2021 पहला उपलब्धि सर्वेक्षण है। इस आकलन को प्रक्रिया कौशल और शिक्षा परिणामों जैसे मानकों के विपरीत छात्रों की शिक्षा को बेंचमार्क करने में इस्तेमाल किया जाएगा। एनएएस 2021, एनईपी 2021 में परिकल्पित कंटेंट और स्मृति आधारित आकलन की तुलना में योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली को लागू करेगा।

कोविड महामारी के चलते स्कूल बंद करने पड़ गए थे और इससे विभिन्न स्तरों पर शिक्षा बाधित हुई थी। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र की सेहत का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए बच्चों के विकास और सीखने की क्षमताओं का मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। स्कूलों के बंद होने का छात्रों की शिक्षा पर असर का मूल्यांकन करने के लिए लॉकडाउन से पहले और बाद में शिक्षा व्यवस्था को आकलन आवश्यक है। शुरुआती ग्रेड के छात्रों पर आकलन को पढ़ने और गणित जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित किया गया है, जिससे समय रहते सुधारात्मक उपाय करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें न सिर्फ ज्ञान संबंधी शिक्षा बल्कि अन्य कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बच्चे महामारी के दौरान घर पर रहते हुए सीख सकते हैं। इसमें पेंटिंग, खाना पकाना, फोटोग्राफी, पढ़ना, बागवानी आदि शामिल हैं। सर्वेक्षण में बढ़-चढ़कर भागीदारी से स्कूलों में सामान्य कामकाज शुरू करने में सहायता मिलेगी।

एनएएस 2021 के नतीजे जिला रिपोर्ट कार्ड, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों रिपोर्ट और राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में तैयार किए जाएंगे। एनएएस से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा परिणामों में खामियों की पहचान करने और सुधार संबंधी कदम उठाने में सक्षम हो जाएंगे। इससे देश में शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों में क्षमता विकास में सहायता भी मिलेगी। आकलन के परिणाम से आगे शोध एवं विकास के दायरे को आगे बढ़ाने वाले प्रमाण और डाटा बिंदुओं का एक समृद्ध भंडार भी उपलब्ध होगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरीन कार्य से हिमाचल की रैंकिंग में आशातीत सुधार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुधार-केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के तरीकों और विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड के अतिरिक्त भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल थे।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र के लिए एक सहयोगी विकास दृष्टि विकसित करने और देश के निवेश माहौल को बढ़ाने पर केंद्रित विचारों के खुले आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बातचीत से निवेश आधारित विकास के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों द्वारा लाए गए दक्षता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण से संभव होगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के दौरान आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आई है और इसमें सुधार के संकेत अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि क्रमश: 9.5 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

शिमला से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश में मुफ्त टीके उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राज्य को अपनी 55 लाख से अधिक योग्य आबादी का टीकाकरण करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को विकास में भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर, 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया, जिसमें 96,720 करोड़ रुपये के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि बैठक के दो महीने के भीतर ही 13,488 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के सम्बन्ध में 236 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरीन कार्य किया है, जिससे राज्य की रैंकिंग सुधार हुआ है और यह 17वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोविड पूर्व के दौर में राज्य की अर्थव्यवस्था में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो कि कोविड-19 के दौरान घटकर माइनस 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, अब यह वृद्धि 5.5 फीसदी हो गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2095 करोड़ रुपये की एशियन विकास बैंक (एडीबी) पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी से इस परियोजना को मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश में हवाई सम्पर्क को मजबूत करने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से आगामी वर्ष के केंद्रीय बजट में मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन की लागत केंद्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में वहन कर रही हैं। उन्होंने भानुपल्ली-बिलासपुर -लेह रेलवे लाइन के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का पूरा खर्च केंद्र वहन करे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब तक लगभग 10,948 मेगावाट बिजली क्षमता का दोहन करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 5497 मेगावाट की परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र को आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वन टाइम एमनेस्टी योजना राज्य में बिजली क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान जे.सी.शर्मा, सचिव जल शक्ति विकास लाबरू, सचिव स्वास्थ्य एवं बागवानी अमिताभ अवस्थी, योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में 18 नई गतिविधियां शामिल

शिमला/शैल। निदेशक उद्योग, राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 में संशोधन कर इसमें 18 नई गतिविधियां शामिल की हैं। अब इस योजना के तहत गतिविधियों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना में अतिरिक्त गतिविधियां शामिल करने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत लघु सेवा व व्यवसायिक उद्यमों की सूची में परिरक्षित चारा (साइलेज) इकाइयों की स्थापना, उन्नत डेयरी विकास परियोजना (10 गाय या भैंसों की एक इकाई), दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, फार्म स्टे/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन, कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण, कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण, सब्जी नर्सरी तैयार करना, ऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला, कृषि उत्पादों का भण्डारण और परिवहन, इन्टरनेट ऑफ थिंग्ज आधारित वर्टिकल फार्मिंग, पेट्रोल पम्प, ईवी चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस, रेशम प्रसंस्करण इकाई, रेशम रीर्लिंग इकाइयां, ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टेंकर सेवाएं, सर्वेयर यूनिट और ड्रिलिंग यूनिट शामिल की गई हैं।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 2000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे कि अब बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। योजना के तहत अभी तक 1350 मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को योजना में शामिल नई व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के तहत प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे सुगम बनाया गया है। इससे युवाओं की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है, साथ ही क्षेत्र के विकास को भी संबल मिल रहा है।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के तहत पहले 85 गतिविधियां उपदान के लिए पात्र थीं, जिसमें अब 18 और नई गतिविधियां शामिल की गई हैं। नई गतिविधियां शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियों का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

तेंदुए मामले में हॉटस्पॉट्स चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर में तेंदुए के आतंक से उत्पन्न स्थिति को लेकर सम्बंधित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने वन मण्डलाधिकारी शिमला की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए जो उन स्थानों (हॉटस्पॉट्स) का पता लगायेगी, जहाँ तेंदुए का खतरा सबसे अधिक है। ऐसे हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर बचाव के ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए इस कमेटी में जिला प्रशासन और नगर निगम शिमला से भी अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में वन विभाग को सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर वहां कैमरा और पिंजरे जल्द लगाये जायें। इसके साथ ही उन्होंने सूचना के लिए एक फ़ोन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए जिस पर सम्बंधित जानकरी दी जा सके और यदि जनता कि तरफ से कोई फीडबैक हो तो इस नंबर पर दी जा सके। उन्होंने वन एवं पुलिस विभाग को खोजी अभियान जारी रखने को भी कहा।

शहरी विकास मंत्री ने शिमला नगर निगम को ऐसे स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के भी निर्देश दिए जिसके लिए शहरी विकास विभाग से नगर निगम को धनराशि प्रदान की जाएगी।

बैठक में प्रमुख सचिव शहरी विकास रजनीश, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, वन विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जे.के.पाठक बने आल इंडिया लियफी मंडल परिषद शिमला के अध्यक्ष

शिमला/शैल। आल इंडिया लियफी मंडल परिषद शिमला का राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन गोपाल मंदिर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ।

इस सम्मेलन में भारतीय जीवन बीमा निगम के 250 अभिकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में आल इंडिया लियफी उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष प्रति पाल सिंह वलेचा तथा महा सचिव आर के चौहान ने हिमाचल प्रदेश मंडल परिषद शिमला की आम चुनाव प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संपन्न करवाया। जे.के.पाठक को फिर से हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष एवं टी एस वर्मा को महासचिव नियुक्त किया गया। प्रति पाल सिंह वलेचा ने एल आई सी प्रबंधन पर अभिकर्ता वर्ग से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। आर के चौहान ने हिमाचल के अभिकर्ताओं को अपने हितों के लिए जागरूक रहने तथा सदा संगठित होकर आवाज उठाने की नसीहत दी। जे के पाठक ने कहा कि वे एल आई सी प्रबंधन के समक्ष अभिकर्ताओं की समस्याओं को मजबूती से रखेंगे तथा अभिकर्ता एवं प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास करेंगे।

टीकाकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों में टीमें गठित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के निर्धारित लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। जिसके लिए प्रदेश में पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान के अलावा पंचायत उप-प्रधान को टीम का सह-अध्यक्ष, पंचायत सचिव सदस्य, पंचायत के सभी वार्ड मेम्बर, आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम का सदस्य बनाया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत स्तर पर गठित की गई यह टीमें अपनी-अपनी पंचायतों में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए पात्र लाभार्थियों को पंचायत के परिवार रजिस्टर के अनुसार चिन्हित करेगी और उनकी सूची तैयार कर उन्हें कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। परिवार रजिस्टर के अलावा अन्य ऐसे पात्र लाभार्थियों को भी इन टीमों द्वारा चिन्हित किया जाएगा, जो पंचायत क्षेत्र में रह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंचायतों में गठित यह टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की मदद भी ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर गठित टीमों द्वारा तैयार की जाने वाली सूचियां टीम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और सभी पंचायतों को 15 नवम्बर, 2021 को प्रस्तावित ग्रामसभा में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित करना होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि ग्रामसभा के अगले दिन ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को पंचायतों द्वारा तैयार की गई सूचियां प्राप्त कर, खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार टीकाकरण केंद्र स्थापित कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आदि के सहयोग से चिन्हित सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में 26 नवम्बर, 2021 की ग्रामसभा में शत-प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाएगें।

मुख्यमंत्री ने अन्तरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिला के रेणुका स्थित रेणु मंच में सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने मेला समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के शुभ अवसर पर प्रकाशित की गई स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए ददाहू में खण्ड विकास कार्यालय, धरतीधार और बचर बाग में आईटीआई (सेमधार) और धरतीधार में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने संगड़ाह में विद्युत बोर्ड का मण्डल कार्यालय खोलने और राजकीय उच्च पाठशाला बागथान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला सत्तार बढ़ो को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और क्षेत्र की दो राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों में से एक है, जिसमें भगवान परशुराम और माता रेणुका के मिलन को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य को समृद्ध संस्कृति का भी प्रतीक है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश इस वर्ष को राज्य की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश आज न केवल पहाड़ी राज्यों, बल्कि देश के बड़े राज्यों के लिए भी एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्ष प्रभावित हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। उन्होंने कहा कि देश भाग्यशाली है कि इस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व देश को मिला है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों और उठाए गए कदमों के कारण ही भारत शेष दुनिया के लिए प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान यह सुनिश्चित किया है कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बिस्तरों आदि की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में जब यह महामारी फैली थी, तो उस समय राज्य में केवल 50 वेंटिलेटर थे। राज्य सरकार ने केन्द्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मामले को उठाया और केन्द्र सरकार द्वारा पीएमकेयर के तहत 500 वेंटिलेटर राज्य को शीघ्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब अढ़ाई लाख हिमाचलियों को विशेष बसों और ट्रेनों के माध्यम से घर वापस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व राज्य में केवल दो ही ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन आज राज्य में 30 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष मेला समिति आर.के. गौतम ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह तथा डांगरा प्रस्तुत कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने मलाणा के प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपये देने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिला के प्राचीन गांव मलाणा का दौरा कर इस वर्ष अक्तूबर में आग लगने की घटना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।

जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 36 प्रभावित परिवारों को 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की और इस सम्बन्ध में परिवारों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 40 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने अग्निकांड की इस घटना में जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, प्रत्येक को अपनी ऐच्छिक निधि से 25 हजार रुपये और आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों के परिवारों को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने मलाणा में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इस संस्थान में शीघ्र ही स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय मलाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए वन निगम द्वारा सात क्यूबिक मीटर टीडी के अतिरिक्त ईंधन की लकड़ी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिका के अन्तर्गत जरी गांव के लिए सिंचाई और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नल से जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

जय राम ठाकुर ने मलाणा के लिए वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छः महीनों के भीतर सड़क कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि गांव का विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने माता रेणुका मन्दिर के लिए किचन सेट के लिए दो लाख रुपये और पिन वैली को पार करने के लिए गांव की ट्रेकर इंद्रा देवी को ऐच्छिक निधि से 25 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

मलाणा गांव के लिए पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के साथ भी बातचीत की।

उन्होंने कहा कि जमलू देवता परिसर के निकट मैदान का भी समुचित रख-रखाव कर इसे विकसित किया जाएगा क्योंकि इस मैदान में सभी धार्मिक कार्य आयोजित किए जाते हैं।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर और बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे और इस दुर्गम गांव का दौरा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का आभार व्यक्त किया।

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन, स्थानीय प्रधान राजू राम, उपायुक्त आशुतोष गर्ग, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने भारतीय पीठासीन अधिकारी सैम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य विधानसभा परिसर का दौरा कर शिमला में 16 से 19 नवम्बर, 2021 तक आयोजित होने वाले 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और 58वें विधायी निकायों के सचिवों के सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और सचिव विधानसभा यशपाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सुरेश भारद्वाज ने दिए कृषक उत्पादक संगठन बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश

शिमला/शैल। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा की प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए विशेष नियम बनाएंगे जिस से किसी भी प्रकार दुविधा न रहे। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के तहत बनाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

भारद्वाज ने शिमला में सहकारिता विभाग, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कृषक उत्पादक संगठन बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से हिमाचल में कृषक उत्पादक संगठन योजना के विस्तार के बारे में चर्चा हुई है। सितम्बर माह में एक योजना बना कर प्रदेश ने एक वर्ष में 100 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा था और पिछले एक महीने में 18 एफपीओ बनाये गए हैं व अन्य पर काम चल रहा है। एक एफपीओ के माध्यम से काम से काम 100 किसान को जोड़ा जायेगा।

बैठक में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। भारद्वाज ने कहा कि अभी कुछ जिले इस योजना में सम्मिलित किये गए हैं। केंद्र सरकार से बाकी जिलों को भी इस योजना के तहत शामिल करने का आग्रह किया जायेगा।

भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सहकारी क्षेत्रों में एफपीओ बनाने को लेकर बल दिया जायेगा और प्रदेश जल्द ही अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जो जिले नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की लक्ष्य सूची में शामिल नहीं हुए हैं वहां भी एफपीओ बना कर कृषि कोष योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।

सुरेश भारद्वाज ने अधिक से अधिक एफपीओ को सहकारी क्षेत्रों में रजिस्टर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता से समृद्धि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह योजना कारगर सिद्ध होगी। केंद्र सरकार ने 6865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से देशभर में नई एफपीओ योजना शुरू की है।

केंद्र सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में सौ संगठन बनाने का फैसला लिया है। हर संगठन में कम से कम 100 किसान-बागवान शामिल करना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में पहले से गठित करीब 40 सहकारी समितियों को एफपीओ के तौर पर परिवर्तित करने की योजना है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि एफपीओ किसानों-बागवानों का एक समूह होगा, जो कृषि-बागवानी उत्पादन कार्य में लगा हो। यह संगठन कृषि और बागवानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। एक समूह बनाकर उसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत करवा सकते हैं। संगठन के माध्यम से खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा, जल्द योजना को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

बैठक में रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं राजेश शर्मा, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय निदेशक राकेश वर्मा, कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हिमाचल पुलिस दो महीनों में 635 लापता लोगों का पता लगाने में रही सफल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा राज्य में इस वर्ष सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस 635 लापता लोगों का पता लगाने में सफल रही।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और उनकी टीम को बधाई दी है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 2010 से 30.09.2021 तक 18,577 लापता व्यक्ति हैं। इनमें से अब तक 17,059 व्यक्तियों का पता लगाया जा चुका है और शेष 1416 व्यक्तियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रेस किए गए व्यक्तियों का कुल प्रतिशत 91.83 है, जो काफी संतोषजनक है। राज्य पुलिस ने व्यक्तियों के लापता होने के कारणों का भी विश्लेषण किया और तदनुसार खोजे गए व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यक परामर्श दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

2018 में प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए आये आवेदनों पर अब तक फैसला क्यों नही

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए नये नियम

शिमला/शैल। इन दिनों प्रदूषण को लेकर दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है उसने पूरे देश का ही नहीं वरन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार तक को इसमें कड़ी फटकार लगायी है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रताड़ना से यह सवाल उठ रहा है कि इसका केंद्र और राज्य सरकारों पर असर कितना हो रहा है। नवम्बर 2017 में एनजीटी ने एक फैसले में शिमला और अन्य प्लानिंग क्षेत्रों में भवन निर्माण को लेकर निर्देश दिये थे कि यहां पर अढाई मंजिल से ज्यादा के निर्माण ना हो। यह भी निर्देश दिए थे कि 1978 से चली आ रही अन्तरिम योजना के स्थान पर नई और स्थायी योजना लाई जाये। लेकिन एनजीटी के इन निर्देशों का कितनी इमानदारी से पालन हुआ है इसका अन्दाजा इस दौरान बने दर्जनों बहुमंजिला भवनों से लगाया जा सकता है। पिछले दिनों कच्ची घाटी में एक आठ मंजिला भवन के गिरने के बाद कुछ दिन सक्रियता नजर आयी जो अब गायब है। बल्कि अब तो नयी योजना लायी गयी है वह एकदम एनजीटी के आदेशों को अंगूठा दिखाने जैसी है क्योंकि इसमें कोर एरिया में भी चार मंजिला निर्माणों की स्वीकृति देने की बात की गयी है। सरकार का टी सी पी विभाग यह योजना ला रहा है। इस पर जनता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रतिक्रिया क्या होगी यह आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अदालत के फैसलों को कितनी अहमियत देती है।

स्मरणीय है कि 2017 में ही सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका भी दायर हुई थी। इस याचिका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिवों की नियुक्तियों को लेकर कोई निश्चित नियम और योग्यता आदि ना होने का मुद्दा उठाया गया था। यह कहा गया था कि राजनीतिक नेताओं को अध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां दी जा रही है और सदस्य सचिवों के पदों पर सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर रही है जो सरकार के इशारों पर नाचते हैं। इस याचिका में आग्रह किया गया था कि इन पदों पर नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता और नियम तय किये जायें। इस पर याचिका में हिमाचल का भी नाम था क्योंकि यहां एक पूर्व विधायक को अध्यक्ष लगाया गया था। इस याचिका पर फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये थे कि छः माह के भीतर यह नियम बनाये जायें और इनके भरने के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए जायें।

यह थे निर्देश Keeping the above in mind, we are of the view that it would be appropriate, while setting aside the judgment and order of the NGT, to direct the Executive in all the States to frame appropriate guidelines or recruitment rules within six months, considering the institutional requirements of the SPCBs and the law laid down by statute, by this Court and as per the reports of various committees and authorities and ensure that suitable professionals and experts are appointed to the SPCBs. Any damage to the environment could be permanent and irreversible or at least long-lasting. Unless corrective measures are taken at the earliest, the State Governments should not be surprised if petitions are filed against the State for the issuance of a writ of quo warranto in respect of the appointment of the Chairperson and members of the SPCBs. We make it clear that it is left open to public spirited individuals to move the appropriate High Court for the issuance of a writ of quo warranto if any person who does not meet the statutory or constitutional requirements is appointed as a Chairperson or a member of any SPCB or is presently continuing as such.

यह फैसला और निर्देश 2017 के अन्त तक जारी हुए थे। इन पर अमल 2018 में शुरू होना था। जयराम सरकार ने इन निर्देशों पर अमल करते हुए अध्यक्ष पद भरने के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किये थे। इस पर कई आवेदन आये हैं। लेकिन चार वर्षों में सरकार इनमें से कोई चयन नहीं कर पायी है। याचिका में यह आग्रह किया गया था कि इन पदों पर नियुक्तियां पांच-पांच वर्ष के लिये की जायें। लेकिन सरकार ने न तो यह नियम ही अब तक सार्वजनिक किये हैं और न ही आये हुये आवेदनों पर चार वर्ष में कोई फैसला लिया है। अब यह मामला फिर उच्च न्यायालय में पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अदालत में कोई कड़े आदेश सुनायेगी। चर्चा है कि जयराम सरकार अभी पदोन्नत हुए मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता को सदस्य सचिव के पद पर तैनात करना चाहती है और उसी के लिए सारी देरी की जा रही है।

हिमाचल में भी गुजरात

.....पृष्ठ 1 का शेष

दो मंत्रियों पर गाज गिराने से कुछ लाभ नहीं होगा बल्कि ऐसे लोग कल को विद्रोही बनकर और नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति में नेता सहित पूरे मंत्रिमंडल को ही गुजरात की तर्ज पर बदल कर ही नया संदेश दिया जा सकेगा।

यह माना जा रहा है कि हर दिन जनता में सरकार की छवि खराब होती जा रही है। क्योंकि इन परिणामों के बाद जो कुछ चण्डीगढ़ में घटा है और उसको लेकर जिस तरह की चर्चाएं उठ रही हैं उससे यह नुकसान लगातार बढ़ता जायेगा यह तय है। फिर नड्डा-शान्ता ने भी नेतृत्व और हार को लेकर कोई ब्यान नहीं दिया है। इनकी खामोशी को भी अलग तरह से देखा जा रहा है

हिमाचल में भी है साइबर ठग हमीरपुर में महिला की गिरफ्तारी से सामने आया मामला

- ❖ हमीरपुर के डेंटिस्ट की पत्नी फेसबुक साइबर ठगी गिरोह की सदस्य, मुकद्दमे दर्ज
- ❖ तीन राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

शिमला/शैल। हमीरपुर के गांव नेरी खग्गल निवासी, मदन लाल कौंडल की पत्नी ध्रुववती उर्फ मोनू व उसके 2 साथियों, सुमित मेंदीरत्ता व प्रिंस आर्या के खिलाफ गुरुग्राम में धारा 66सी, 66डी, 419, 420, 34 व 120बी के अंतर्गत साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। छः और पीड़ितों ने भी अपने अपने शहरों के पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई हैं जिनकी जांच करके मुकद्दमे दर्ज किए जायेंगे। आरोप है कि ध्रुववती ने फरीदाबाद में रहने वाले सुमित मेंदीरत्ता व प्रिंस आर्या के साथ मिलकर, पीड़ितों के फेसबुक मैसेंजर के फर्जी अकाउंट बनाकर, विदेश में रहने वाले एनआरआई भारतीयों को अपनी मां की झूठी बीमारी का संदेश भेजा और छः लोगों से, पंजाब नेशनल बैंक की दरुही, हमीरपुर ब्रांच के अपने दो बैंक खातों में लगभग तीन लाख रूपये जमा करवा लिए। रुपए मंगाने के लिए, ध्रुव ने हमीरपुर में ही रहने वाले अपने एक दोस्त जीवन कुमार के पेटीएम खाते का भी इस्तेमाल किया जो बाद में ले लिए। उसके बाद ध्रुव व प्रिंस आर्या ने ठगी में अपने हिस्से की रकम काटकर बाकि रूपए सुमित मेंदीरत्ता के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिये। पुणे के एक पीड़ित की शिकायत पर पुणे साइबर पुलिस द्वारा आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जिन्हें कुछ समय बाद ध्रुववती ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से खुलवा कर बाकि के सारे रूपए निकाल लिए और खाते बंद करा दिए। इस गिरोह के कुख्यात सरगना सुमित मेंदीरत्ता के खिलाफ पहले से ही देश विदेश में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी के दर्जनों मामले दर्ज है और वह चार-पांच दफा जेल की हवा खा चुका है। ध्रुववती के पिता कृष्णलाल कौशल नादौन के बूनी गांव के निवासी हैं और शादी ब्याह में लग्न आदि करते हैं। छोटा भाई कार्तिक कौशल मोहाली में सैलून चलाता है। पति मदन लाल झानियारी में के.के. डेंटल लैब चलाता है और अच्छे पैसे कमा लेता है। फिर पता नहीं क्यों साइबर ठगी के अनैतिक व गैरकानूनी तरीके से ज्यादा व आसान रुपए कमाने की जरूरत पड़ी?

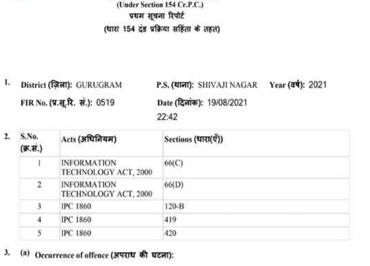

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (ज़िला): GURUGRAM P.S. (थाना): SHIVAJI NAGAR Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0519 Date (दिनांक): 19/08/2021 22:42

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	66(C)
2	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	66(D)
3	IPC 1860	120-B
4	IPC 1860	419
5	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

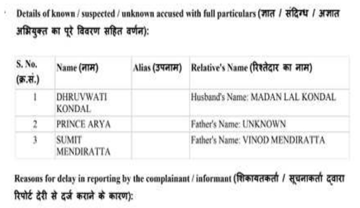

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	DHRUVWATI KONDAL		Husband's Name: MADAN LAL KONDAL
2	PRINCE ARYA		Father's Name: UNKNOWN
3	SUMIT MENDIRATTA		Father's Name: VINOD MENDIRATTA

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

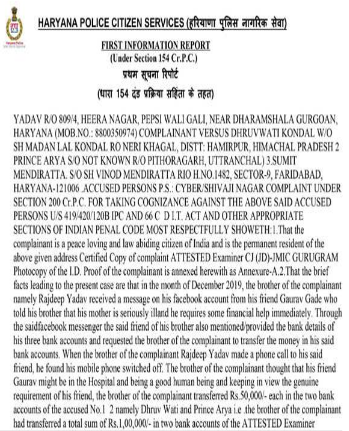

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

YADAV R/O 809/4, HEERA NAGAR, PEPSI WALI GALI, NEAR DHARAMSHALA GURGOAN, HARYANA (MOB.NO.: 8800350974) COMPLAINANT VERSUS DHRUVWATI KONDAL W/O SH MADAN LAL KONDAL RO NERI KHAGAL, DISTT: HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH 2 PRINCE ARYA S/O NOT KNOWN R/O PITHORAGARH, UTTRANCHAL) 3.SUMIT MENDIRATTA. S/O SH VINOD MENDIRATTA RIO H.NO.1482, SECTOR-9, FARIDABAD, HARYANA-121006 .ACCUSED PERSONS P.S.: CYBER/SHIVAJI NAGAR COMPLAINT UNDER SECTION 200 Cr.P.C. FOR TAKING COGNIZANCE AGAINST THE ABOVE SAID ACCUSED PERSONS U/S 419/420/120B IPC AND 66 C D I.T. ACT AND OTHER APPROPRIATE SECTIONS OF INDIAN PENAL CODE MOST RESPECTFULLY SHOWETH:1.That the complainant is a peace loving and law abiding citizen of India and is the permanent resident of the above given address Certified Copy of complaint ATTESTED Examiner CJ (JD)-JMIC GURUGRAM Photocopy of the I.D. Proof of the complainant is annexed herewith as Annexure-A.2.That the brief facts leading to the present case are that in the month of December 2019, the brother of the complainant namely Rajdeep Yadav received a message on his facebook account from his friend Gaurav Gade who told his brother that his mother is seriously illand he requires some financial help immediately. Through the saidfacebook messenger the said friend of his brother also mentioned/provided the bank details of his three bank accounts and requested the brother of the complainant to transfer the money in his said bank accounts. When the brother of the complainant Rajdeep Yadav made a phone call to his said friend, he found his mobile phone switched off. The brother of the complainant thought that his friend Gaurav might be in the Hospital and being a good human being and keeping in view the genuine requirement of his friend, the brother of the complainant transferred Rs.50,000/- each in the two bank accounts of the accused No.1 2 namely Dhruv Wati and Prince Arya i.e .the brother of the complainant had transferred a total sum of Rs.1,00,000/- in two bank accounts of the ATTESTED Examiner